

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

# (असाघारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 28 धप्रैल, 2007/8 वैशाख, 1929

## हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रशिक्षण एवं विदेशी समनुदेशन विभाग

**ग्रधिसूचना** 

शिमला-2, 18 अप्रैल, 2006

- 1. संक्षिप्त नाम श्रौर प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा (प्रथम संशोधन) नियम, 2007 है।
- (ii) ये नियम राज्यत, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे तथापि नियम 23(2) के उपबन्ध इस श्रिधसूचना के जारी होने की तारीख के एक वर्ष पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2(2)(vi) का संशोधन ——(i) हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1979 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 2 के उप-नियम (2) के खण्ड (v) के पश्चात् परन्तु खण्ड (vi) से पूर्व निम्नलिखित खण्ड (vi) प्रन्तःस्थापित किया जाएगा, प्रथित :——

"(vi) समस्त ऐसे अन्य अराजपित कर्मचारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कम से कम दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनकी अगली प्रोन्नित या स्थानन (प्लैसमैंट), जब कभी भी हो, उन्हें राजपित पंक्ति में ले ग्राएगी।"

- (ii) उक्त नियमों के नियम 2 के उप-नियम (2) के विद्यमान खण्ड (vi) को खण्ड (vii) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।
- 3. नियम 4 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (1) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात :—

विभागीय परीक्षा बोर्ड का गठन निम्नलिखित से होगा :--

 "(i) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार
 ग्रध्यक्ष

 (ii) प्रधान सचिव/सचिव (राजस्व)
 " सदस्य

 (iii) प्रधान सचिव/सचिव (उद्यान)
 " सदस्य

 (iv) प्रधान सचिव/सचिव (कार्मिक)
 " सदस्य

 (v) प्रधान सचिव/सचिव (वित्त)
 " सदस्य

(vi) प्रधान सिचव /सिचव (प्रिशिक्षण) : सदस्य (vii) महानिदेशक/निदेशक, हिमाचल प्रदेश, लोक प्रशासन संस्थान : सदस्य :

परन्तु अध्यक्ष, जब कभी म्रावश्यक हो, सरकार के किसी प्रधान सचिव/सचिव को भ्रौर/ या सम्बद्ध विभागाध्यक्ष को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा।"।

4. नियम 12(2) का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 12 के उप-नियम (2) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, ग्रर्थातु:—

''सचिव द्वारा ग्रवार्ड-सूचियों की प्राप्ति पर परिणाम संकलित किया जाएगा श्रौर ऐसी सिफारिशों सहित, ै जसी वह ग्रावश्यक समझें, ग्रध्यक्ष के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जाएगा ।''

5. नियम 17 का संशोधन — "उक्त नियमों" के नियम 17 के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्न-लिखित रखा जाएगा, ग्रर्थात् -—

"ग्रन्चित साधन.—उक्त अधिकारी, जिसे या तो परीक्षा के समय या तत्पश्चात् श्रन्चित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, के मामले की तत्काल उत्तर-पुस्तिका(ग्रों) ग्रोर किसी अन्य दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य सहित सचिव को तत्काल रिपोर्ट की जाएगी जो ऐसे ग्रधिकारी के विरूद्ध की जाने वाली कार्रवाई विनिश्चत करने के लिए मामला अध्यक्ष के समक्ष रखेगा। ग्रध्यक्ष निम्नलिखित में से कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:—

(i) ग्रधिकारी को पूर्ण परीक्षा में ग्रनुत्तीर्ण घोषित किया जा सकेगा;

(ii) अधिकारी को एक या अधिक पेपरों में अनुत्तीर्ण घोषित किया जा सकेगा;

(iii) ग्रिधिकारी को भविष्य में होने वाली परीक्षामों में बैठने से विवर्णित किया जा सकेगा ; श्रीर-

- (iv) कोई ग्रन्य कार्रवाई, जिसे अध्यक्ष, सम्बद्ध विभाग को उसके विरुद्ध करने के लिए सुज्ञाना चाहे :
- परन्तु अध्यक्ष कोई शास्ति अधिरोजित करने से पूर्व अभ्यर्थी को मौखिक या लिखित में अभ्यानेदन करने का अवसर दे सकेगा।"
- 6. नियम 23(2) का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 23 के विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, ग्रर्थात :---

"राजपितत अधिकारी से जिसने 55 वर्ष की ग्रायु प्राप्त कर ली हो, दक्षता रोध पार करने/ प्रवीणता वेतन वृद्धि/ग्रागामी देय, उच्चतर वेतनमान ग्रीर सेवा में स्थाईकरण के प्रयोजनों के लिए, समय-समय पर यथा संशोधित इन नियमों के ग्रधीन विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की ग्रपेक्षा नहीं की जाएगी तथापि राजपितत ग्रधिकारी, उनकी ग्रायु को विचार में लाए बिना, ग्रागामी प्रोन्नित, जब भी देय हो, ऐसी परीक्षा पास करने के पश्चात ही प्राप्त करने के हकदार होंगे।"

ग्रादेश द्वारा,

एस 0 विजय कुमार, प्रधान सचित्र।

[Authoritative English text of the Government notification No. Per-(Trg.)A-(4)-2/92-II, dated the 18th April, 2007 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

### TRAINING AND F. A. DEPARTMENT

### **NOTIFICATION**

Shimla-171 002, the 18th April, 2007

No. Per. Trg.-A (4)-2/92-II-Part.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. Per (Trg.) B (12) 40/95, dated the 13th March, 1997, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(i) These rules shall be called the Himachal Pradesh Departmental Examination (First Amendment) Rules, 2007.
- (ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh. However, the provisions of Rules 23(2) shall come into force after one year from the date of issue of the notification.
- 2. Amendment of rule 2(2) (vi).—(i) After clause (v) but before clause (vi) of sub-rule (2) of Rule 2, of the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997 (hereinafter referred the "said rules") the following clause (vi) shall be inserted, namely:—

X 1,

"(vi) All such other Non-Gazetted officials who have put in not less than 10 years of regular service in connection with the affairs of the State of Himachal Pradesh and whose next promotion or placement as and when it takes place shall put them in a Gazetted rank".

(vii)

- (ii) The existing clause (vi) of sub-rule (2) of Rule 2 shall of "said rules" be renumbered as clause (vii).
- 3. Amendment of Rule 4.—For the existing provisions of sub-rule (1) of Rule 4 of the said Rules, the following shall be substituted, namely:

"The Board of Departmental examination shall consist of:

- The Chief Secretary to the Government Chairman
- Principal Secretary/Secretary (Revenue) (ii)Principal Secretary/Secretary (Hosticulture) (iii)

Member Member

(iv)Principal Secretary/Secretary (Personnel) (v) Principal Secretary/Secretary (Finance)

- Member Member
- Principal Secretary/Secretary (Training) (vi) Director General/Director H. P. Institute of Public Administration
- Member Member

Provided that the Chairman may co-opt a Secretary/Pr. Secretary to the Government and/or a Head of Department concerned as member whenever necessary".

- 4. Amendment of Rule 12(2).—For the existing provision of sub-rule (2) of rule 12 of the said Rules, the following shall be substituted, namely:-
  - "The result will be compiled by the Secretary on the receipt of award lists and will be placed before the Chairman for approval with such recommendations, as he may deem necessary."
- Amendment of Rule 17—For the existing provisions of Rule 17 of the "Said Rules." the following shall be substituted, namely:-
  - "Unfair means.—The case of an officer who either at the time of examination or subsequently is found to have used unfair means will be reported to the Secretary forthwith alongwith the answer book(s) and any other documentary or oral evidence, who shall place the matter before the Chairman for deciding the action to be taken against such officer. The Chairman may impose any of the following penalties :-
  - The officer may be declared failed in the entire examination;
  - The officer may be declared fail in one or more papers;
  - Debarring the officer from appearing in future examinations; and (iii)
  - Any other action, which the Chairman may like to suggest to the Department (iv)concerned to be taken against him:

Provided that before imposing any of the panalties, the Chairman may give an opportunity to the candidate to make representation, orally or in writing.

- Amendment of Rule 23(2).—The existing sub-rule (2) of Rule 23 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—
  - "A Gazetted Officer on the attainment of 55 years of age shall not be required to pass the Departmental Examination prescribed under these Rules, as amended from time to time for the purposes of crossing the Efficiency Bar/Proficiency step up/Higher Scale, next due and confirmation in the service. However, Gazetted Officers irrespective of their age shall get further promotion whenever due only after passing such examination.".

By order,

S. VIJAY KUMAR, Principal Secretary.